सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप–प्रत्यारोप

कुल मिलाकर स्थिति यह हो गई है कि महामारी के इस दौर में जब सबको एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करने की जरूरत थी, तब विभिन्न दलों और अलग–अलग सरकारों के अलग–अलग सुर निकल रहे हैं।

नवीन शर्मा ।।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार पर कोरोना की दूसरी लहर से निपटने में पूरी तरह नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए मांग की है कि सरकार तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाकर विस्तार से पूरी स्थिति स्पष्ट करे। यकीनन सरकार उनके आरोपों का भरपूर खंडन करेगी, लेकिन मीटिंग के उनके सुझाव पर गौर करना ठीक रहेगा। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप–प्रत्यारोप चलते रहते है। लेकिन देश में कोरोना की दूसरी लहर ने जो हालात पैदा कर दिए हैं, वे किसी भी सूरत में सामान्य नहीं कहे जा सकते। दवाएं, अस्पताल, आईसीयू बेड, ऑक्सिजन, वैक्सीन हर मोर्चे पर कमियां दिख रही हैं। लोग उन कमियों की वजह से जूझते, बिलखते और मरते देखे जा रहे हैं। सरकार अपने स्तर पर कोशिश कर रही है, लेकिन उन कोशिशों की सीमाएं साफ दिख रही हैं। इसके उलट ऑक्सिजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन सही वक्त पर और सही मात्रा में उसे मुहैया कराने की चुनौती बनी हुई है।

इसी क्रम में कई गैरबीजेपी शासित राज्यों की सरकारों का केंद्र सरकार से विवाद भी बढ़ता दिख रहा है। कुल मिलाकर स्थिति यह हो गई है कि महामारी के इस दौर में जब सबको एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करने की जरूरत थी, तब विभिन्न दलों और अलग–अलग सरकारों के अलग–अलग सुर निकल रहे हैं। ऐसे में यह पहली जरूरत है कि सभी राजनीतिक दलों और उनसे जुड़ी सरकारों में तालमेल बनाया जाए। इसका सबसे अच्छा उपाय यही हो सकता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जल्द से जल्द एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए जिसमें सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ सारे तथ्य रखे और देश की राजनीतिक बिरादरी को विश्वास में ले।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को विश्वास में लेने की दिशा में पहला कदम होता है जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेना। हालांकि कोरोना संक्रमण शुरू होने के बाद से दो बार सर्वदलीय बैठक हो चुकी है। पहली बैठक पिछले साल 8 अप्रैल को हुई थी जब देश में 21 दिनों का पहला लॉकडाउन चल रहा था। दूसरी सर्वदलीय बैठक 4 दिसंबर को हुई जब वैक्सीन जल्द ही तैयार हो जाने की उम्मीद बन चुकी थी।

हालात उस वक्त भी बुरे थे, लेकिन तब न तो सरकारी तंत्र ऐसा असहाय नजर आ रहा था और न ही आम लोगों में ऐसी निराशा थी। इसलिए आज पहले से भी ज्यादा जरूरी है कि सरकार सभी राजनीतिक दलों के नेतृत्व को साथ लेने की पहल करे। इन दलों के चुनावी हित अलग–अलग हो सकते हैं, लेकिन आखिर सबको इसी देश में, इसी जनता के बीच राजनीति करनी है, उसी के समर्थन से आगे बढ़ना है। आज जब बात देश की है, आम जनता की है तो सबका दायित्व है कि छोटे–छोटे हितों से ऊपर उठें। सब उठेंगे भी, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की है, इसीलिए पहल भी उसे ही करनी चाहिए।

घोर तपस्या

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा। यहां पर जल को भगवान विष्णु के घोर तपस्या से उत्पन्न पसीने की बूंद भी समझा जा सकता है। पुराण में यह भी माना गया है कि जगत को रचने की इच्छा से भगवान विष्णु ने जल की रचना की और उसमें उन्होंने अपने अंश का बीज डाला। एक हजार साल बीतने पर वह बीज एक स्वर्णमय अण्ड के रूप में परिणत हो गया। फिर भगवान विष्णु स्वयं उस अण्ड में प्रविष्ट हो गए। इसके बाद उस अण्ड से सूर्य, धरती, स्वर्गलोक, ब्रह्मा, सातों पर्वत, सातों समुद्र सब निकले। उत्पत्ति और विनाश दोनों में जल उपस्थित है। पुराणों में बार–बार उल्लैख आया है कि जब प्रलय काल आता है उस समय सारा जगत अंधकार में खो गया था। ऐसा अंधकार कि ना तो उसके विषय में कोई कल्पना की जा सकती थी ना कोई वस्तु जाना जा सकता था।

संपादकीय

बदला–बदला रवैया

पाकिस्तानी सत्ता–प्रतिष्ठान का रवैया काबुल की गनी सरकार के प्रति बदला–बदला–सा लग रहा है। हालांकि अब भी इमरान खान ने अमेरिका को अपने हवाई अड्डों की वह सुविधा देने से इनकार कर दिया है, जिसके तहत वह अफगानिस्तान में होने वाले तालिबानी हमलों को कमजोर कर सकता है। पाकिस्तान का यह पसोपेश समझ में आता है। उसके कान इस तथ्य ने भी खड़े कर दिए हैं कि आजकल भारत ने तालिबान से गुपचुप संपर्क बढ़ा लिए हैं। तालिबान ने साफ–साफ कहा है कि कश्मीर समस्या से उसका कुछ लेना–देना नहीं है। वह भारत का आंतरिक मामला है। पाकिस्तानी फौज और नेताओं को पता है कि तालिबानी पठान बहुत ही स्वाभिमानी और स्वतंत्र स्वभाव के लोग होते हैं। सत्तारूढ़ होने के बाद क्या मालूम वे कहने लग जाएं कि पेशावर को अपनी राजधानी बनाएंगे और 1893 में खिंची डूरेंड सीमा–रेखा को रद्द करेंगे। हो सकता है यह इस्लामी अमीरात चीन के उइगुर मुसलमानों के पक्ष में भी मुहिम छेड़ दे। पाकिस्तान का परम मित्र चीन इसे कैसे बर्दाश्त करेगा?

तालिबान नेता मुल्ला उमर ने 1999 में हमारे अपहृत जहाज को कंधार से छुड़वाने में भी मदद की थी। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में भारत और पाकिस्तान अपनी फौजें काबुल भेज दें तो तालिबान थोड़ा–बहुत लिहाज जरूर दिखाएंगे। तालिबान व गनी सरकार में समझौता तो फिर हुवा–हुवाया ही है। काबुल में होने वाला भारत–पाक सहयोग कश्मीर के स्थायी हल का रास्ता भी तैयार कर देगा।

बाइडन ने उन्हें आश्वस्त किया है कि अमेरिका उसे 3.3 बिलियन डॉलर देने वाला है। लेकिन यह भी कहा है कि अब अफगान सरकार को अपने पांव पर खड़े होना है। अमेरिका अफगानों का साथ छोड़ नहीं रहा है।

बाइडन की मजबूरी

वेदप्रताप वैदिक।।

अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी और सीईओ डॉ. अब्दुल्ला की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से भेंट हो चुकी है। उसके बावजूद अमेरिकी सरकार अपने इस फैसले पर कायम है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजें 11 सितंबर तक वापस चली जाएंगी। सिर्फ 650 जवान काबुल में टिके रहेंगे, जो अमेरिकी दूतावास की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। जहां तक काबुल हवाई अड्डे की सुरक्षा का सवाल है, उसकी जिम्मेदारी तुर्की की सरकार ले रही है।

राष्ट्रपति बाइडन अपना पद संभालने के बाद अभी तक न तो भारत और न ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिले हैं। फिर भी वह अफगानिस्तान के नेता से मिले तो इसीलिए क्योंकि वहां से अमेरिकी फौज की वापसी इन दोनों देशों के लिए जबर्दस्त धक्का है। अमेरिका ने पिछले 20 वर्षों में उसने वहां अरबों डॉलर बहाए, सैकड़ों सैनिकों की जिंदगी कुर्बान की और अपने आप को विश्व–शक्ति प्रचारित करने के बावजूद अफगान तालिबान से मात खाई।

अफगान लोग भी कम परेशान नहीं। वे नहीं चाहते कि अमेरिकी और नाटो फौजें उनके देश से अभी वापस जाएं। गनी और अब्दुल्ला यह बात काबुल में तो कहते ही रहे हैं, उन्होंने वॉशिंगटन में भी अपना पूरा जोर लगाया होगा,

इसमें जरा भी शक नहीं है लेकिन राष्ट्रपति जो बाइडन की भी मजबूरी है। उन्होंने वापसी की तारीख 1 मई से खिसकाकर 11 सितंबर कर दी, यही क्या कम है? इन पांच महीनों में काबुल सरकार अपनी सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर सकती थी। वह कर भी रही है। उसे चिंता है कि उसके ढाई–तीन लाख फौजियों का रख–रखाव कैसे होगा?

बाइडन ने उन्हें आश्वस्त किया है कि अमेरिका उसे 3.3 बिलियन डॉलर देने वाला है। लेकिन यह भी कहा है कि अब अफगान सरकार को अपने पांव पर खड़े होना है। अमेरिका अफगानों का साथ छोड़ नहीं रहा है। वह उनकी मदद करेगा, लेकिन उन्हें अब खुद तय करना होगा कि वे अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे। बाइडन के चिकने–चुपड़े आश्वासनों के साथ गनी और अब्दुल्ला काबुल लौट आए हैं, लेकिन उन्हें पता है कि पिछले साल अमेरिका की मध्यस्थता से जो समझौता तालिबान और काबुल सरकार के बीच हुआ था, वह हवा में उड़ चुका है। तालिबान के हमले जारी हैं। अफगानिस्तान के लगभग एक–तिहाई यानी 100 जिलों में तालिबान के पदचाप सुनाई दे रहे हैं। 40 जिलों पर तो उनका कब्जा है ही।

तालिबान संगठन मूलतः गिलजई पठानों का है। उनसे अफगानिस्तान के ताजिक, उजबेक, हजारा, तुर्कमान, शिया, मू–ए–सुर्ख जैसे अल्पसंख्यक बहुत डरे हुए हैं। उनका अंदाजा है कि छह महीने या साल भर में तालिबान काबुल पर कब्जा कर लेंगे। फौज का भी कुछ भरोसा नहीं। उसमें ज्यादातर जवान पठान हैं। वे रातोरात अपनी निष्ठा बदल लेंगे। अभी–अभी काबुल में हजारा संप्रदाय के लोगों ने विशाल प्रदर्शन करके बताया कि उन्होंने अपने मोहल्लों को हथियारबंद कर लिया है। अनेक अफगान मित्र, जो कि नेता भी हैं और मालदार भी, फोन करके मुझसे पूछ रहे हैं कि हम रहने के लिए भारत आ जाएं तो कैसा रहेगा? उन्हें डर है कि तालिबान के सत्तारूढ़ होते ही काबुल में कत्ले–आम शुरू हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद काबुल में वैसी ही अराजकता फैल सकती है, जैसी ब्रिटिश और रूसी फौजों की वापसी के बाद फैली थी। इस तथ्य को पाकिस्तानी नेताओं से बेहतर कौन समझ सकता है।

सूडोकु बवाल-5407

★★★★☆ मध्यम

6	9			7	4		8	
	8	5	6	2			4	9
7						6		3
	3	9	5				1	
1				8				5
	6				2	9	3	
4		7						2
8	2			5	9	1	7	
	1		2	3			5	8

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3x3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु बवाल -5406 का हल

6	5	3	9	1	7	2	8	4
9	1	8	2	6	4	3	7	5
7	4	2	5	3	8	1	9	6
3	7	1	6	9	2	4	5	8
8	6	9	1	4	5	7	2	3
5	2	4	8	7	3	9	6	1
2	9	5	4	8	1	6	3	7
4	3	6	7	5	9	8	1	2
1	8	7	3	2	6	5	4	9

अपना ब्लॉग

काबुल और तालिबान के बीच समझौता करवाए?

मोहन। पिछले महीने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष कमर जावेद बाजवा स्वयं काबुल पहुंचे और उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में कोई अतिवादी, उग्रवादी या तालिबान राज कायम हो जाए, ऐसा वह नहीं चाहते। यदि सचमुच ऐसा है तो वह अपनी सरकार को प्रेरित क्यों नहीं करते कि वह काबुल सरकार और तालिबान के बीच समझौता करवाए? अगर पाकिस्तान सही ढंग से पहल करे तो तालिबान और गनी सरकार के बीच समझौता करवाने में उसकी भूमिका अमेरिका से अधिक सार्थक और प्रभावशाली हो सकती है। यह ठीक है कि तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान उस तरह का रवैया नहीं अपना सकता, जैसा कुछ समय पहले तक अमेरिका ने अपना रखा था। पाकिस्तान की सक्रिय सहायता के बिना तालिबान सफल हो ही नहीं सकते थे। आज भी पाकिस्तान में तालिबान के तीन संगठन उसके शहरों के नाम से चल रहे हैं। पेशावर शूरा, क्वेटा शूरा और मिरानशाह शूरा।